केस-दर-केस लेनी पड़ती इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और केस चीफ जस्टिस एन वी रमना को रेफर कर दिया गया है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही यह प्रकरण सही दिशा में आगे बढ़ेगा।

मनोज शाह।।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ठीक ही चिंता जताई है कि एक–एक करके आठ राज्य सीबीआई को जांच–पड़ताल के लिए दी गई आम इजाजत वापस ले चुके हैं और इसका देश की इस प्रमुख जांच एजेंसी के कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। हाल ही में सीबीआई डायरेक्टर ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके बताया था कि पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मिजोरम द्वारा आम सहमति वापस लिए जाने से सीबीआई को इन राज्यों में किसी तरह की जांच–पड़ताल शुरू करने से पहले केस–दर–केस इजाजत लेनी पड़ती है।

आलम यह है कि 2018 से लेकर जून 2021 के बीच किए 150 अनुरोधों में से सीबीआई मात्र 18 फीसदी मामलों में जांच की अनुमति हासिल कर सकी है। गौर करने की बात है कि मिजोरम (जहां मिजो नैशनल फ्रंट की सरकार है) को छोड़ दें तो सीबीआई से आम सहमति वापस लेने वाले इन तमाम राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। इन राज्यों की शिकायत है कि सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए किया जा रहा है और इसीलिए वे हर केस का मेरिट देखने के बाद ही उसे जांच करने की इजाजत देने या नहीं देने का फैसला करेंगे।

अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और केस चीफ जस्टिस एन वी रमना को रेफर कर दिया गया है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही यह प्रकरण सही दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि ऐसी उलझनें तब पैदा होती हैं, जब केंद्रीय एजेंसियों की विश्वसनीयता का ग्राफ नीचे जाता है। सीबीआई जैसी एजेंसी के कामकाज को लेकर बना अविश्वास जहां विरोधी दलों के नेताओं के मन में आशंकाएं पैदा करता है, वहीं उनमें से कुछ को यह ढाल देता है कि वे राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए अपने या अपने लोगों के खिलाफ चल रही जेनुइन जांच भी रुकवाने की कोशिश करें।

दोनों ही स्थितियों का सबसे बुरा असर इस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा की जा रही जांच–पड़ताल पर पड़ता है। सीबीआई डायरेक्टर के हलफनामे के मुताबिक भी राज्य सरकारों की इजाजत के अभाव में लंबित पड़े मामलों में कई बड़े वित्तीय घोटालों से जुड़े हैं जो इतने बड़े हैं कि देश की इकॉनमी को भी प्रभावित कर सकते हैं। बहरहाल, इसमें शक नहीं कि इस मामले के कानूनी पहलू भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कानून के जरिए निकाला गया कोई भी फॉर्म्युला व्यवहार में काम तभी करेगा, जब उस पर अमल अच्छी तरह होगा। और अमल का सूत्र इस बात में है कि सेंट्रल एजेंसियों को प्रफेशनल तरीके से काम करने दिया जाए। इस बिंदु पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और सेंट्रल एजेंसियों के अंदर की ब्यूरोक्रेसी तीनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं और अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ये तीनों ठीक से निभाएं तभी बात बनेगी।

हे ईश्वर

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

अंत में जब उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो निराश होकर ईश्वर के सामने घुटने टेक दिए– "हे ईश्वर, मुझ पर दया करो। अगर तुम मुझे एक सौ खजूर दोग तो मैं आधे तुम्हारी सेवा में अर्पित कर दूंगा।" जब उसने नेत्र खोले तो सचमुच उसके आगे खजूरों का ढेर लगा हुआ था। वह आदमी बहुत प्रसन्न हुआ और खजूरों की गिनती करने लगा। पूरे पचास थे। उसने सभी खजूर पेट भर खा लिए और बोला– "हे ईश्वर! मुझे नहीं मालूम था कि तुमने अपने हिस्से के खजूर पहले ही रख लिए हैं। तुम तो हिसाब–किताब में बड़े पक्के हो।" इतना कहकर वह चालाक आदमी वहां से चलता बना। एक किसान था। उसके पास एक बकरा और दो बैल थे। बैलों से वह खेत जोतने का काम लेता। दोनों बैल दिन भर कड़ी मेहनत करके खेतों की जुताई करते थे।

संपादकीय

तीसरी लहर का खतरा

कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर है। संसद में कोरोना पर चली 12 घंटे की बहस एक अवसर के रूप में सामने आई थी, जिसमें सांसद अपने इलाकों के अनुभव साझा कर कोरोना को रोकने के नए सुझाव दे सकते थे। सरकारी तंत्र की कमियों की तरफ इशारा कर सकते थे, परंतु अधिकतर सांसदों ने इस महत्वपूर्ण मौके को गंवा दिया। और वह भी तब जब वायरस का नया संस्करण कभी भी कोरोना की तीसरी लहर में तब्दील हो सकता है। इस देश के लोग राजनेताओं से बेहतर की उम्मीद करते हैं। देश को विभिन्न हितधारकों विशेषकर राजनेताओं के बीच एक स्वस्थ चर्चा की तत्काल आवश्यकता है। जहां तक सत्ता पक्ष के सांसदों का सवाल है तो लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में, सरकार के अच्छे कामों को सकारात्मक तरीके से उजागर करना उनका काम है और इसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। परंतु महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, वायरस लगातार अपना रूपरंग बदल रहा है, वायरस की संक्रामकता के साथ–साथ उससे निपटने की चुनौती भी बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस का नवीनतम संस्करण ओमिक्रॉन अधिकांश लोगों के दिलो–दिमाग पर छाया हुआ है। इसकी अत्यधिक संक्रामकता ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। हालांकि अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि यह डेल्टा संस्करण से अधिक घातक और खतरनाक नहीं है। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच पर कोरोना पर हुई बहस में जिस तरह का व्यवहार राजनेताओं ने, खासकर विपक्षी सांसदों ने किया, उससे छोटे राजनीतिक हित तो साधे जा सकते हैं लेकिन राष्ट्रहित का नुकसान हो सकता है।

अब दुनिया भर में तेजी से फैल रहे, अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन की शक्ल में एक नई चुनौती सामने है। इस खतरे से मुकाबले के लिए एक गहन आत्मचिंतन, आपसी विमर्श और एक राष्ट्रीय दृढ़ संकल्प चाहिए।

विपक्ष का अजेंडा

ओमप्रकाश गुप्ता।।

कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। स्वदेशी टीके का विकास और करोड़ों भारतीयों को टीका लगाने का महाअभियान निस्संदेह प्रशंसनीय है। आंकड़े बताते हैं कि कोविड–19 की दूसरी लहर के बाद भारत की स्थिति कई विकसित देशों की तुलना में बेहतर है। परंतु अब दुनिया भर में तेजी से फैल रहे, अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन की शक्ल में एक नई चुनौती सामने है। इस खतरे से मुकाबले के लिए एक गहन आत्मचिंतन, आपसी विमर्श और एक राष्ट्रीय दृढ़ संकल्प चाहिए। विभिन्न विचारधाराओं वाले एक विकासशील देश में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय संकल्प खड़ा करना बेहद दुष्कर है। जब तक देश एक अनुशासन से नहीं बंधेगा, ओमिक्रॉन वैरिएंट का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सरकार के हर मंत्रालय और विभाग को लयबद्ध तरीके से काम करना होगा। उपयुक्त नीतियां बनाकर हर वर्ग को जोड़ना होगा।

दूसरी तरफ विपक्ष से भी रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा है। पर अफसोस की बात है कि विपक्षी पार्टियों का अजेंडा कुछ और ही लगता है। वे दलगत फायदे के लिए राष्ट्रीय मुद्दों का राजनीतिकरण करने से नहीं चूक रहे। विपक्ष के लिए हर बहस का राजनीतिकरण करना राष्ट्रीय

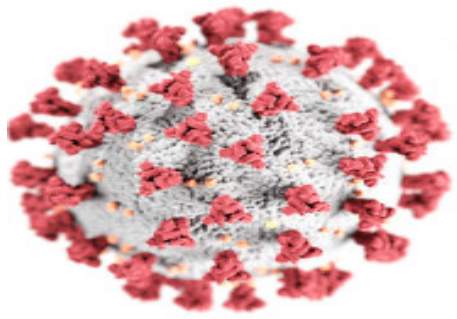

हित से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।

लोकसभा में 3 दिसंबर को लगभग 12 घंटों तक कोविड–19 पर चर्चा हुई। सरकार ने इस मुद्दे पर जन–प्रतिनिधियों को बोलने का पर्याप्त अवसर दिया। आधी रात तक चली बहस के दौरान 96 सदस्यों ने अपनी बात रखी। उम्मीद की जा रही थी कि देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों से रचनात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। लेकिन बहस का नतीजा निराशाजनक रहा। विपक्ष ने यहां भी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। विपक्ष को समझना होगा कि राजनीतिक फायदे के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने से न तो कोरोना भागेगा और न ही देश का भला होगा।

आरोपों की राजनीति में तथ्य और तर्क कहीं खो से गए। हास्यास्पद दावे किए गए, एक विपक्षी सांसद ने कहा कि कोविड–19 की वजह से भारतीय रेलवे का निजीकरण कर दिया गया। अब उन्हें कौन समझाए कि भारतीय रेलवे पहले की तरह अब भी भारत सरकार के अधीन काम कर रही है। और कुछ गतिविधियों में निजी क्षेत्र को जोड़ने का कोरोना वायरस से कोई लेना–देना नहीं है। एक वामपंथी सांसद ने सलाह दी कि टीकाकरण प्रमाणपत्र पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तस्वीर लगनी चाहिए न कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की।

हम सब जानते हैं कि एक भारतीय कंपनी ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमोदित किया है। फिर भी एक विपक्षी सांसद ने घोषणा कर डाली कि वैश्विक पर्यवेक्षक महसूस करते हैं कि कोविड से संबंधित विज्ञान में हमारा योगदान बहुत छोटा है। एक अन्य सांसद ने कुछ बेसिर पैर का गुणा–भाग करने की नाकाम कोशिश की। कितने लोगों को टीका लगा और कितनी खुराक दी गई, इसको वह सही से समझ ही नहीं पाए। टीकाकरण की संख्या का गलत अनुमान लगा कर सांसद महोदय बोले कि वह आधिकारिक दावों से चकित हैं। ऐसे ही एक सांसद ने प्रवासी श्रमिकों के घर लौटने का मुद्दा उठाया। यहां तक तो फिर भी ठीक था, पर जब उन्होंने इसे देश के विभाजन के बाद का अब तक का सबसे बड़ा पलायन बताया तब साफ हो गया कि वह राजनीतिक अवसरवाद से ग्रसित हैं।

अष्टयोग-5112

	3		1		2	
3	29	6	37		31	1
	2			5	6	
5	30	1	30	4	31	6
	6				3	2
2	33	4	31	3	30	7
	1		5		4	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5111 का हल

7	6	1	4	2	3	5
2	28	4	33	7	35	4
1	2	5	6	4	7	3
5	28	3	38	6	34	1
4	2	6	3	5	1	7
3	31	2	31	1	30	6
6	1	7	4	3	5	2

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

नजर रखना विपक्षी दलों का काम

मोहन। सरकार की खामियों पर नजर रखना विपक्षी दलों का काम है लेकिन यह रचनात्मक तरीके से किया जाना चाहिए था। भारत सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया, जो ज्यादातर लोगों के लिए मुफ्त था। महामारी से निपटने में राज्य प्रशासन निश्चित रूप से कहीं बेहतर कर सकता था लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत का प्रदर्शन, स्वयंभू भविष्यवक्ताओं द्वारा किए गए निराशापूर्ण पूर्वानुमानों से कहीं बेहतर रहा। कोरोना के खिलाफ जंग की शुरुआत भारत ने मात्र 1 परीक्षण केंद्र से की थी लेकिन तीन महीने के भीतर इसे बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया। नौ महीने में देश ने प्रतिदिन एक करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पांच बार छुआ। आज देश में 15,000 से अधिक समर्पित कोविड अस्पताल और बीमारी के परीक्षण एवं ट्रैकिंग के लिए एक प्रभावी प्रणाली काम कर रही है, जिसने भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।